Sharma

1. इंडेपेंडेंट थॉट v/s भारत संघ - 2017 D.B. SC

IPC sec 375 का अपवाद (2) ART-14, 15 and 21 का उल्लंघन करता है अतः निरस्त किये जाने योग्य है तथा POCS Act के प्रावधानों के विरुद्ध भी है।
"किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से कम की नहीं है।

2. MS Meters and Instrumentation Pvt Ltd v/s Kanchan Mehta 2017

यदि Accused चैक धनराशि + ब्याज तथा व्ययों सहित नियत तिथि पर जमा कराने को तैयार है तो court मामले का उपशमन कर सकता तथा Accused को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है यदि कार्यवाही जारी रखे जाने योग्य है।

3. शत्रुघ्न चौहान v/s भारत संघ - 2014

ART-72/161 मे क्षमादान की शक्ति का J.R. इस आधार पर कि दया याचिका निस्तारण मे अयुक्तियुक्त, अस्पष्टीकृत तथा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो Death Penalty को L.I. मे convert किया।

4. श्याम नारायण चौकसे v/s भारत संघ - 2018

सिनेमा हाल में फीचर फिल्म प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पर्दे पर राष्ट्रगान बजाना आदेशात्मक नहीं वैकल्पिक व निर्देशात्मक है तथा दिव्यांग को सम्मान में खड़े होने से छूट दी जायेगी।

5. समीर विश्वास राव भारद्वाज v/s नमिता समीर भारद्वाज - 2017

D.V. Act sec-17 मे साझी गृहस्थी पति-पत्नी दोनों के नाम है तो D.V. के अभियोजन में पति को निवास आदेश जारी कर पति को निर्णय तक अलग रहने का निर्देश दिया जा सकता है।

6. शायरा बानो v/s भारत संघ 2017 संविधान पीठ 3:2

तीन तलाक/तलाक उल बिद्दत को अपास्त किया जाता है तथा शरियत अधि० 1937 की धारा 2 को समाप्त किया जाता है क्योंकि यह ART 14 के violation मे है तथा ART 15 व 21 का उल्लंघन करता है तथा ART 25(1), 26 B तथा 29 द्वारा संरक्षित नहीं है।

क्रमशः

7. राजेश शर्मा vs UP राज्य 2017
498A (IPC) के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व मामले की गंभीरता के कारण अप्रत्याशित वृद्धि होने पर सामान्य दिशा निर्देश जारी -
पूर्व में: प्रीति गुप्ता vs झारखंड सरकार - 2010
अर्नेश कुमार vs बिहार राज्य - 2014 - गिरफ्तारी के बारे में
ललिता कुमारी vs U.P सरकार 2013 - अशमनीय के शमनीय बनाने निर्देश - विधिक

8. राकेश कुमार पाल vs असम राज्य 2017
Defult Bail CRPC 167(2)(i) के में 60/90 में Invest. पूरा न हो

9. Justice के० एस० पुत्तास्वामी vs भारत संघ - 2017 9 सदस्यी संविधान पीठ
[M.P शर्मा vs सतीशचन्द्र जिला मजि० दिल्ली 1954 - संविधान में उल्लिखित
खड़क सिंह vs UP राज्य - 1954 एकान्तता का right संविधान द्वारा संरक्षित नहीं
को over Rule कर - एकान्तता का अधिकार Art-21 मूल अधिकार है
उक्त निर्णय आधार कोई योजना के प्रवर्तन से संबंधित है।

10. अमरदीप सिंह vs हरवीन कौर 2017
HMA की धारा 13(ख) के (i) (ii) में 6 माह की प्रतीक्षा अवधि आदेशात्मक नहीं वरन निर्देशात्मक है यदि अन्य शर्तें (Sec-9 के प्रावधान विफल, पक्षकारों ने भरण-पोषण, अभिरक्षा तथा अन्य लम्बित मामलों को निपटा लिया है) पूर्ण होती है तो विचारण न्याया. स्वविवेकानुसार अवधि में छूट दे सकता है।

11. सेव लाइफ फाउन्डेशन vs भारत संघ 2016 (समरीटेन्स लॉ)
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार, तत्काल मदद तथा हॉस्पिटल पहुँचाने वाले व्यक्ति (समरीटेन्स) को संरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी (10) गाइडलाइन्स

12. शफी मोहम्मद vs हिमाचल प्रदेश - 2017
यदि कोई पक्षकार जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणित कराना चाहता है। परन्तु उसकी पहुँच उस यन्त्र तक नहीं है। जिससे वह Document उत्पादित किया गया था तो Evid act के sec-65B में ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना व प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होगा। उक्त Judgement ने हरपाल सिंह @ छोटा vs पंजाब 2016 को Overrule किया जिसमें Mobile Details हेतु प्रमाणपत्र जरूरी था

13. सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार vs भारतसंघ - 2018

S.C. का IPC की धारा 498A के संबंध मे पूर्व निर्णय राजेशशर्मा vs UP. 2017 द्वारा जारी किये दिशा निर्देशों को निरस्त किया गया। जो अन्वेषण गिरफ्तारी व जमानत के संबंध मे है। - Case no. 07 देखे।

14. नवतेजसिंह जौहर vs भारतसंघ 2018 - संविधान पीठ

IPC की धारा - 377 आंशिक रूप से असंवैधानिक - ART 14 व 19 का उलंघन करती है। अत एल॰जी॰बी॰टी॰ समुदाय के अधिकारो तक निरस्त,

① दो वयस्को के मध्य सहमतिजन्य यौन कृत्य को दण्डनीय बनाये - unco… शेष - सभी मामलो मे IPC. 377 संवैधानिक है।

इस निर्णय द्वारा S.C. का पूर्व निर्णय सुरेशकुमार कौशल vs नाज फाउण्डेशन निरस्त किया गया

Homosexual - पुरुष का पुरुष से
Hetrosexual - पुरुष का महिला से
Lesbian - महिला का महिला से

} तीनो ही स्थितियो मे असंवैधानिक

पुरुष या महिला का पशु के साथ संबंध बनाना - IPC 377 मे संवैधानिक।

15. जोसफ सिने vs भारत संघ 2018 - संविधान पीठ

IPC की धारा - 497 (जारता) के offence मे - केवल पुरुष को दोषित करे तथा महिला को दोषी न माने जाने के कारण - असंवैधानिक है। तथा ART. 14, 15 तथा 19 का violation करती है। साथ ही CRPC की धारा 198(2) प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भी अवैध होने से निरस्त

16. महेन्दर चावला vs भारत संघ - 2018 ART-32

"साक्षी संरक्षण योजना" 2018 लागू - जबतक संसद द्वारा इस संबंध मे विधि नही बना दी जाती तबतक ART 141/142 के अधीन सामान्य विधि होगी "सरकार vs आशाराम बापू" के मामले मे साक्षियो की हत्या, धमकी तथा उत्प्रेरणा के आधार पर दाण्डिक मामलो मे साक्षियो के संरक्षण हेतु विधि

17. स्वप्निल त्रिपाठी vs सुप्रीम कोर्ट of India - 2018

व्यापक जनहित मामले तथा कुछ आपवादिक मामलो मे S.C की सुनवाई कार्यवाहियो का सजीव व सीधा प्रसारण स्वीकार किया गया परन्तु इस संबध मे खुला न्यायालय" court की गरिमा, शिष्टाचार को ध्यान रखा जायेगा (CRPC sec 327 एव CPC की धारा - 153-बी) के अन्तर्गत

18. तहसीन एस॰ पूनावाला vs भारत संघ 2018

MOB Linching के मामलों मे पूरे देश के पुलिस प्रशासन हेतु दिशा निर्देश जारी करना पड़ा जिसमे पशुतस्करो, डायन महिला तथा लव जेहादी के आरोपी की अनियंत्रित भीड़ द्वारा पिटाई की जाती है।

शक्ति वाहिनी vs भारत संघ - 2018

Honour killing IPC में अपराध है अतः ऐसी घटनाओं पर IPC की धारा 141, 143, 503, 506 के साथ अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन सुनिश्चित किया जाये दिशा निर्देश जारी किये

कामन काज सोसायटी vs भारत संघ - 2018

विशेष परिस्थितियों में Passive यूथानासिया को मान्यता दी गई H.C. के निर्देशों के अन्तर्गत doctors की राय द्वारा जीवनरक्षक उपकरणों को हटाया जा सकता है जो रोगी को कृत्रिम श्वास देकर जीवित रखते हैं

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण vs भारत संघ 2014 (NALSA)

सरकार किन्नरों (हिजड़ों) को देश में तृतीय लिंग की पहचान तथा देश के अन्य नागरिकों की तरह सभी विधिक व संवैधानिक अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करे।

लिली थामस एवं लोक प्रहरी vs भारत संघ - 2013

जनप्रतिनिधित्व अधि 1951 की धारा 8(4) असंवैधानिक है किसी भी अदालत से दोषी करार पाये जाने और 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त होगी

3. पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) vs भारत संघ 2013

मतदाता को निर्वाचक को नकारने का अधिकार मिलना चाहिये मतपत्र या EVM में NONE of Above (NOTA) का विकल्प होना चाहिये

4. शैलेष मनुभाई परमार vs भारत व चुनाव आयोग (ECI) 2018

NOTA की व्यवस्था देश के आम चुनाव के लिए लागू किया जा सकता है किन्तु NOTA की व्यवस्था को "राज्यसभा के चुनाव हेतु" लागू किया जाना ART 80(4) के लक्ष्यों व भावनाओं के उल्लंघन में होगा।

शफी मोहम्मद vs हिमाचल प्रदेश 2018

25. हरपाल सिंह @ छोटा v/s पंजाब राज्य - 2016 SC
फोन कालस की डिटेल तब तक साक्ष्यों के रूप में ग्राह्य नहीं होंगे जबतक वे साक्ष्य अधि० की धारा - 65B (4) के अन्तर्गत यथा तरीके से प्रमाणित न हो

26. अनवर P.V v/s पी० के० बशीर 2014 SC
इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के साक्ष्य तबतक ग्राह्य नहीं होगे जब तक कि वे Evid act की धारा - 65 बी (4) के अन्तर्गत यथा प्रारूप मे प्रमाणित न हो अर्थात प्रमाणपत्र न पेश किया गया है

27. रवेन्द्र सिंह v/s त्रिपुरा राज्य 2017 SC
पीडित व्यक्ति को CRPC की धारा 372 के परन्तुक (दि०31.12.09 से प्रभावी) के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति के ORDER के विरुद्ध अपील करने का सारवान और स्वतंत्र अधिकार है किन्तु ऐसी अपील H.C. की अनुमति से ही किया जा सकता है (सत्यपाल सिंह v/s M.P राज्य - 2015) के निर्णयानुसार धारा 372 के परन्तुक को धारा 378(3) के साथ पढ़ा जाना चाहिये

28. हरदीप सिंह v/s पंजाब राज्य - 2014 SC. (CONSTITUTIONAL BENCH)
किसी offence की जांच व विचारण के दौरान साक्ष्य से प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने जो Accused नहीं है कोई offence किया हो जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का Accused के साथ विचारण किया जा सकता है वहाँ COURT उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है
(i) FIR मे नाम न हो
(ii) FIR के PART 2 मे नाम हो
(iii) FIR मे नाम था लेकिन charge sheeted नहीं किया गया
(iv) Person जो Discharge किया गया
(v) केवल Chief exam. के आधार पर ही जोडा जा सकता है यदि Record पर Material उपलब्ध है Cross Exam जरूरी

29. धर्मपाल v/s हरियाणा 2014 SC (CONST. Bench)
मामले की सुपुर्दगी के बाद sec. 193 मे सेशन न्याया० संज्ञान ले

जोड़ने के लिए sec 319 CrPC के साक्ष्य का इन्तजार नहीं कर सकता वह पुलिस द्वारा file documents के आधार पर विचार करके अतिरिक्त अभियुक्त को समन कर सकता है। CrPC 319 के अन्तर्गत सेशन न्यायालय साक्ष्य अभिलेखन के स्तर पर सीधे (Direct) संज्ञान ले सकता है।

30 ललिता कुमारी v/s उत्तरप्रदेश सरकार - 2008/2014 (Const. Bench)

154 CrPC के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर FIR दर्ज करने हेतु कोई पुलिस अधिकारी बाध्य है या प्रारंभिक जांच करना आवश्यक है -

1. यदि सूचना से संज्ञेय offence कारित होना प्रकट होतो FIR दर्ज करना आज्ञापक है प्रारम्भिक जाँच जरूरी नहीं
2. यदि सूचना से संज्ञेय offence प्रकट नहीं होता तो प्रारम्भिक जाँच जरूर
3. यदि जाँच से संज्ञेय offence प्रकट होतो FIR दर्ज करना जरूरी तथा FIR दर्ज करना जरूरी नहीं होतो इसबात की सूचना 7 days मे पीड़ित को कारण सहित दिया जाना जरूरी
4. संज्ञेय offence प्रकट होनेपर FIR दर्ज न करनेपर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है।
5. जिन मामलो मे प्रारम्भिक जाँच जरूरी है.—
   (क) वैवाहिक विवाद (घ) वाणिज्यिक अपराध
   (ख) पारिवारिक विवाद (ङ) चिकित्सा उपेक्षा के मामले
   (ग) भ्रष्टाचार के मामले (च) मामले जहां दाण्डिक अभियोजन का प्रारम्भ अत्यधिक देरी से किया गया है।